GAD SAMVEDNA 17 November, 2019

अनुसंधान से वनों की दशा सुधारेगा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

लिए कार्य करेगा। नई दिल्ली में श्री को रोपित करने के लिए प्रदान किया प्रकाश जावडेच्कर, माननीय वन एवं जलवायु जाएगा। वक्ष चारा, ईंधन-काष्ठ, अकाष्ठ परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 15 वन उत्पाद, वन्य फलों, मुदा नमी, नवम्बर 2019 को राष्ट्रीय प्रतिपुरक जैवविविधता, संरक्षण एवं व्याधियों के वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधि महत्वपूर्ण विषय-क्षेत्रों का भी निवारण ाकरण की प्रबंध निकाय की बैठक में डॉ. किया जाएगा। वन आनुवंशिक संसाधन सुरेश गैरोला, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. (एफ.जी.आर.) संरक्षण महत्ता का एक ने विस्तत योजना "पारिस्थितिकीय अन्य क्षेत्र है जिस पर राष्ट्रीय स्तर संवहनीयता तथा उत्पादकता संवृद्धि के संतति व भविष्य के वंशों के जीन भण्डार लिए वानिकी अनुसंधान का सदढीकरण" के संरक्षण के लिए कार्य किया रोपणियों की उत्पादकता में संवृद्धि के प्रजातियों के कृत्तकों एवं किस्मों का प्रौद्योगिकीयों के लिए पहुँच (आउटरीच) को प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय प्रतिपुरक जाएगा।'राज्य रेड्ड कार्य योजना'' को लिए कार्य करेगा। नई दिल्ली में प्रकाश विकास किया जाएगा तथा कृषकों एवं कार्यक्रम सबसे कमजोर कडी रहा है। वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधि तैयार करने के लिए राज्य वन विभागों जावडेकर, वन एवं जलवाय परिवर्तन) राज्य वन विभागों को रोपित करने के इसका सदढीकरण इस योजना 'भा.वा. किरण के प्रबंध निकाय ने भा.वा.अ.शि.प. का क्षमता निर्माण इस योजना का तीसरा मंत्री की अध्यक्षता में 15 नवम्बर 2019 लिए प्रदान किया जाएगा। वक्ष चारा, अशिप की वानिकी विस्तार योजना' के की योजना का 313.67 करोड़ रुपये को घटक है। कपि नीति की तर्ज पर वन को राष्ट्रीय प्रतिपुरक वनीकरण निधि ईधन–काष्ठ, अकाण्ड वन उत्पाद, वन्य माध्यम से होगा। हित्तधारकों तक पहुँचना पूर्णतः अनुमोदित किया। भारत की प्रमुख नीति अनुसंधान सरकार को विभिन्न प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण की फलों, मुदा नमी, जैवविविधता, संरक्षण ही इस घटक की मुख्य विषय–वस्त है। वानिकी परिषद के इतिहास में यह एक नीतियों की संकल्पना तथा वर्तमान वन प्रबंध निकाय की बैठक में डॉ. सुरेश एवं व्याधियों के महत्वपूर्ण विषय-क्षेत्रों नवीन क्षेत्रों में वैज्ञानिक क्षमताओं की ऐतिहासिक क्षण है कि इसके सुत्रपात से नीतियों के प्रभावों के अध्ययन में आवश्यक गैरोला, महानिदेशक, भा.वा.आ.शि.प. ने का भी निवारण किया जाएगा। वन संवुद्धि के लिए मानव संसाधन विकास अब तक इस मुख्य योजना को सरकार नीति निर्देशन प्रदान करेगा। इस पहलु विस्तुत योजना ''पारिस्थितिकीय आनुवंशिक संसाधन (एफ.जी.आर.) को इस योजना के माध्यम से संबोधित द्वारा वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार हेतु को योजना के चतुर्थ घटक द्वारा विवेचना संवहनीयता तथा उत्पादकता संवृद्धि संरक्षण महत्ता का एक अन्य क्षेत्र है किया जाएगा। भावाअशि.प. संस्थान अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय महत्त्व की जाएगी। वानिकी अनुसंधान में के लिए वानिकी अनुसंधान का सुद्द जिस पर राष्ट्रीय स्तर संतति व भविष्य पहले से ही देश की 13 मुख्य नदियों की की अनुसंधान समस्याओं के सम्बोधन के प्रौद्योगिकीयों के लिए पहुँच (आउटरीच) ढीकरण'' को प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय 🛛 के वंशों के जीन भण्डार के संरक्षण के जीर्णोद्वार योजना के निर्माण पर कार्य लिए वानिकी अनुसंघान को अति आवश्यक कार्यक्रम सबसे कमजोर कडी रहा है। प्रतिपुरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं लिए कार्य किया जाएगा।'राज्य रेड्र कर रहे हैं। नई दिल्ली में 15 नवम्बर वित्तपोषण की प्रापित होगी जिसका प्रत्यक्ष इसका सुदुढीकरण इस योजना 'भा.वा. नियोजन प्राधिकरण के प्रबंध निकाय ने कार्य योजना'' को तैयार करने के लिए 🛛 2019 को अनुमोदित नई योजना राष्ट्रीय 🛛 सम्बन्ध देश के वन आरोग्यता तथा वन 🛛 अ.शि.प. की वानिकी विस्तार योजना'' भा.वा.अ.शि.प. की योजना का 313.67 राज्य वन विभागों का क्षमता निर्माण महत्ता के मुद्दों के सम्बोधन के लिए भा. आधारित लोगों की आजीविका एवं कृषि के माध्यम से होगा। हितधारकों तक करोड़ रुपये को पूर्णतः अनुमोदित किया। इस योजना का तीसरा घटक है। 🛛 वा.अ.शि.प. की संवद्ध क्षमता में और अधि पर होगा। इस योजना के माध्यम से, भा. पहुँचना ही इस घटक की मुख्य भारत की प्रमुख यानिकी परिषद के 👘 कृषि नीति की तर्ज पर वन नीति 🛛 क विस्तुत रूप से जडती है। भारतीय 🛛 वा.अ.शि.प. तथा इसके संस्थान 31 मुख्य 🛛 विषय–वस्तु है। नवीन क्षेत्रों में वैज्ञानिक इतिहास में यह एक ऐतिहासिक क्षण है अनुसंधान सरकार को विभिन्न नीतियों वानिकी अनुसंधान एवं ज्ञिक्षा परिषद (भा. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान क्षमताओं की संवृद्धि के लिए मानव संसाध कि इसके सूत्रपात से अब तक इस की संकल्पना तथा वर्तमान वन नीतियों वा.अ.शि.प.) देहरादन, देशभर में फैले परियोजनाओं पर कार्य करेंगे जिससे ान विकास को इस योजना के माध्यम से मुख्य योजना को सरकार द्वारा वानिकी के प्रभावों के अध्ययन में आवश्यक इसके नौ अनुसंधान संस्थानों तथा पाँच आरोग्यता व उत्पादकता में सुधार होगा संबोधित किया जाएगा (भा.वा.अ.शि.प. अनुसंधान एवं विस्तार हेतु अनुमोदित नीति निर्देशन प्रदान करेगा। इस पहलु केन्द्रों के माध्यम से पारिस्थितकी को तथा वनों एवं रोपणियों के निम्नीकरण की संस्थान पहले से ही देश की 13 मुख्य किया गया है। राष्ट्रीय महत्त्व की अनुसंक को योजना के चतुर्थ घटक द्वारा विवेचना वहन करने के लिए राष्ट्रीय महत्ता के पुनर्प्रापि होगी। महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों नदियों की जीणॉद्वार योजना के निर्माण ान समस्याओं के सम्बोधन के लिए की जाएगी। वानिकी अनुसंधान में वानिकी अनुसंधान मुद्दों तथा भारतीय वनों के कुन्तकों एवं किस्मों का विकास किया पर कार्य कर रहे हैं।

एवं रोपणियों की उत्पादकता में संवृद्धि के जाएगा तथा कृषकों एवं राज्य वन विभागों

ान एवं शिक्षा परिषद (भा.वा.अ.शि.प.) भा.वा.अ.शि.प. तथा इसके संस्थान 31 देहरादन, देशभर में फैले इसके नौ मुख्य अखिल भारतीय समन्वित अनुसंध अनुसंधान संस्थानों तथा पाँच केन्द्रों के ाान परियोजनाओं पर कार्य करेंगे जिससे माध्यम से पारिस्थितकी को वहन करने आरोग्यता व उत्पादकता में सधार होगा के लिए राष्टीय महत्ता के वानिकी तथा वनों एवं रोपणियों के निम्नीकरण अनुसंधान मुद्दों तथा भारतीय वनों एवं की पुनर्प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण वृक्ष महानिदेशक डॉ. सुरेश गैरोला

देहरादन, गढ संवेदना वानिकी अनुसंधान को अति आवश्यक

संवाददाता। भारतीय वानिकी अनुसंह वित्तपोषण की प्राप्ति होगी जिसका प्रत्यक्ष

ान एवं शिक्षा परिषद (भा.वा.अ.शि.प.) सम्बन्ध देश के वन आरोग्यता तथा वन

देहरादन अनुसंधान से वनों की दशा आधारित लोगों की आजीविका एवं कृषि को सुधारेगा। भारतीय वानिकी अनुसंध पर होगा। इस योजना के माध्यम से,

THE HAWK 17 November, 2019

ICFRE Will Improve Status Of Forests Through Research Interventions



Dehradun: Dehradun based Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) along with its nine re-search institutes and five centres spread across the country will be working on forestry research issues of national importance for sustaining ecology and enhancing productivity of Indian forests and plantation. In the meeting held at New Delhi on 15 November 2019 of the governing body of National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (Na-tional-CAMPA) chaired by Shri Prakash Javadekar, Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change, Dr. S.C. Gairola, Director Gen-eral, ICFRE presented the detailed scheme "Strengthening Forestry Research for Ecological Sustainability and Pro-ductivity Enhance-ment". The National CAMPA Governing body approved Rs. 313.67 crores scheme of ICFRE in toto that will be spread over five years. This is the water-shed moment in the history of the premier forestry Council of India that such a major scheme has been approved by the Govern-ment for forestry research and extension

since its formation in 1988. Forestry research will get the much required funds for addressing the research problems of na-tional importance that will have direct bearing on the forest health of the country and livelihood of people dependent on forest and agriculture. Through this scheme, ICFRE and its Institutes will be working on 31 major All India Coordi-pated Beacareh Deviated nated Research Projects that will improve health, productivity and restore degradation of forests and plantation. Clones and varieties of important tree species will be developed and provided to farmers and state forest departments for plantation. Im-portant topics of tree fodder, fuelwood, NTFP, wild fruits, soil moisture, biodiversity, conservation and diseases will also be addressed.

Forest Genetic Resource (FGR) Conservation is another area of importance that will be taken up at the national level to conserve the gene pool for posterity and future generation.

Capacity building of State Forest Departments for preparing "State REDD+ Action Plan" is the third component of scheme.

Forest Policy Research on the lines of Agriculture policy will provide the much needed policy guidance to the Government in designing various policies and studying the impacts of existing forest policies. This aspect will be dealt by the 4th component of the scheme. Outreach program for extension of technologies had been the weakest link in the forestry research. This will be strengthened through this scheme by adopting the "Forestry Extension Plan of ICFRE". Reaching out to stakeholders is the centre theme of this component of ICFRE. Human resource

Human resource development to enhance the scientific capabilities of scientists in newer areas will also be addressed through the scheme. ICFRE institutes

are already working on the preparation of reju-



venation plans of 13 major rivers of country. The new scheme approved on 15th November 2019 at New Delhi further adds to its enhanced capabilities to address the issues of national importance.

THE HIMACHAL TIMES 17November, 2019

ICFRE Dehradun to improve status of forests through research interventions

(HTNS) Dehradun based Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) along with its nine research institutes and five centres spread across the country will be working on forestry research issues of national importance for sustaining ecology and enhancing productivity of Indian forests and plantations.

In the meeting held at New Delhi on 15 November of the governing body of National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (National-CAMPA) chaired by Prakash Javadekar, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Dr SC Gairola, Director General, ICFRE presented the detailed scheme "Strengthening Forestry Research for Ecological Sustainability and Productivity Enhance-

DEHRADUN, NOV16 ment". The National CAMPA Governing body approved Rs 313.67 crores scheme of ICFRE that will be spread over five years. This is a notable moment in the history of the pre-mier Forestry Council of India that such a scheme has been approved by the Government for forestry research and extension since its formation in 1988.

It is being hoped that Forestry research will now get the much required funds for addressing the research problems of national importance that will have direct bearing on the forest health of the country and livelihood of people dependent on forest and agriculture. Through this scheme, ICFRE and its Institutes will be working on 31 major All India Coordinated Research Projects that will improve health, productivity and restore degradation of forests and plantation. Clones and varieties of

important tree species will be developed and provided to farmers and state forest departments for plantation. Important issues of tree fodder, fuelwood, NTFP, wild fruits, soil moisture, biodiversity, conservation and diseases will also be addressed.

Forest Genetic Resource' (FGR) Conservation is another area of importance that will be taken up at the national level to conserve the gene pool for posterity and future generation.

Capacity building of State Forest Departments for preparing "State REDD+Action Plan" is the third component of scheme.

Forest Policy Research on the lines of Agriculture policy will provide the much needed policy guidance to the Government in designing various policies and studying the impacts of existing forest policies. This aspect will be dealt by the fourth component of the scheme.

DAINIK JAGRAN 17 November, 2019

कैंपा में आइसीएफआरई को मिलेंगे 313 करोड़

जागरण संवाददाता, देहरादूनः भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) को कैंपा (कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी) से क्षतिपूरक वनीकरण के लिए 313.67 करोड़ रुपये मिलेंगे।केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की बैठक में यह निधि स्वीकृत की गई।

आइसीएफआरई के महानिदेशक डॉ. एससी गैरोला ने कहा कि उनकी तरफ से बैठक में 'पारिस्थितिकीव संवहनीव व उत्पादकता संवृद्धि के लिए वानिकी अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण' विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। वन संवर्धन की दिशा में परिषद की विशेषज्ञता को देखते केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जावड़ेकर की बैठक में दी गई स्वीकृति, क्षतिपूरक वनीकरण की दिशा में करेंगे काम

हुए ही यह निधि स्वीकृत की गई है। महानिदेशक ने बताया कि परिषद के अधीन वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) समेत देशभर के नौ संस्थान कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से प्रतिपूस्क वनीकरण व इसके तमाम पहलुओं पर काम किया जाएगा। साथ ही संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर की 31 परियोजनाओं पर काम कर लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। ताकि वनों की आरोग्यता बढ़ाने व वन संवर्धन में अपेक्षित परिणाम हासिल किए जा सकें।

THE PIONEER 18 November, 2019

ne pioneei DEHRADUN | MONDAY | NOVEMBER 18, 2019

ICFRE to improve status of forests through research interventions

National CAMPA governing body approves ₹313.67 crore scheme of ICFRE



The Dehradun-based Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), along with its nine research institutes and five centres spread across the coun-try, will be working on forestry research issues of national importunce for sustaining aco try, will be working on forestry research issues of national importance for sustaining ccol-ogy and enhancing productiv-ity of Indian forests and plan-tations. In the meeting of the the governing body of National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (National-CAMPA), chaired by Union Minister for Environment, Forests and Climate Change, Prakash Javadekar in New Delhi recently, the ICFRE director general, SC Gairola, presented the detailed scheme for strengthening forestry research for ecological sus-tainability and productivity enhancement. The National CAMPA gov-erning body approved ₹313.67 crore scheme of ICFRE in toto that will be spread over five years.

years.

According to officials, this is the watershed moment in the is the watershed moment in the history of the premier forestry council of India with such a major scheme being approved by the Government for forestry research and extension since its formation in 1988.

formation in 1988. Forestry research will get the much-required funds for addressing the research issues of national importance that will have direct bearing on the forest health of the country and livelihood of people depen-dent on forest and agriculture.



ACCORDING TO OFFICIALS, THIS IS THE WATERSHED MOMENT IN THE HISTORY OF THE PREMIER FORESTRY COUNCIL OF INDIA WITH SUCH A MAJOR SCHEME BEING APPROVED BY THE GOVERNMENT FOR FORESTRY RESEARCH AND EXTENSION SINCE ITS FORMATION IN 1988 FORESTRY RESEARCH WILL GET THE MUCH-REQUIRED FUNDS FOR ADDRESSING THE RESEARCH ISSUES OF

NATIONAL IMPORTANCE THAT WILL HAVE DIRECT BEARING ON THE FOREST HEALTH OF THE COUNTRY AND LIVELIHOOD OF PEOPLE DEPENDENT ON FOREST AND AGRICULTURE

Through this scheme, the ICFRE and its institutes will be working on 31 major All India

Coordinated Research Projects

Coordinated Research Projects that will improve health, pro-ductivity and restore degrada-tion of forests and plantation. Clones and varieties of impor-tant tree species will be devel-oped and provided to farmers and State forest departments for

plantation. Important topics of tree fodder, fuelwood, NTFP, wild fruits, soil moisture, biodiver-sity, conservation and diseases

sity, conservation and diseases will also be addressed. Forest Genetic Resource (FGR) Conservation is anoth-er area of importance that will be taken up at the national level to conserve the gene pool for

1

F

posterity and future generation. Capacity building of State Forest Departments for prepar-ing State REDD+ action plan is the third component of scheme. Forest policy research on the lines of agriculture policy will provide the much-needed policy guidance to the Government in designing var-ious policies and studying the impacts of existing forest poli-cies.

cies. This aspect will be dealt by the fourth component of the scheme. Outreach programme the total in Contract programme for extension of technologies had been the weakest link in the forestry research efforts. This will be strengthened through this scheme by adopting the forestry extension plan of ICFRE? Reaching out to stake-holders is the centre theme of this component of ICFRE. Human resource develop-ment to enhance the scientific capabilities of scientists in newer areas will also be addressed through the scheme. ICFRE institutes are already working on the preparation of rejuvenation plans of 13 major rivers of country.

rejuvenation plans of 13 major rivers of country. The new scheme approved further adds to its enhanced capabilities to address the issues of national importance.

RASHTRIYA SAHARA 17 November, 2019

आईसीएफआरई एवं शिक्षा परिषद करेगी इस दिशा में कार्य, 313.67 करोड़ रुपये अनुमोदित

अनुसंधान से सुधरेगी देश में वनों की दशा

🔳 सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) नवीन अनुसंधान द्वारा वनों की दशा सुधारेगा। परिषद के देशभर में स्थित नौ अनुसंधान संस्थान व पांच केंद्र पारिस्थितकी को वहन करने के लिए राष्ट्रीय महत्ता के वानिकी अनुसंधान मुद्दों, भारतीय वनों व रोपणियों की उत्पादकता में संबृद्धि के लिए कार्य करेंगे।

परिषद के महानिदेशक डा. सुरेश गैरोला ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रवंधन एवं नियोजन प्राधिकरण की प्रवंध निकाय की वैठक में पारिस्थितिकीय संवहनीयता तथा उत्पादकता संवृद्धि के लिए वानिकी अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण विषय पर विस्तत प्रस्ततिकरण दिया।

वहीं रॉप्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रवंधन एवं नियोजन प्राधिकरण के प्रवंध निकाय ने आईसीएफआरई की योजना का 313.67 करोड़ रुपये को पूर्णतः अनुमोदित किया। परिषद के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक क्षण है कि जवकि



इस मुख्य योजना को भारत सरकार द्वारा वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार हेतु अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व की अनुसंधान समस्याओं के संवोधन के लिए वानिकी अनुसंधान को अति आवश्यक वित्तपोषण की प्रापित होगी, जिसका प्रत्यक्ष संवंध देश के वन आरोग्यता तथा वन आधारित लोगों की आजीविका व कृषि पर होगा।

महानिदेशक डा. गैरोला ने वताया कि इस योजना के माध्यम से आईसीएफआरई व सहयोगी संस्थान 31 मुख्य अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करेंगे, जिससे आरोग्यता व उत्पादकता में सुधार होगा तथा वनों एवं रोपणियों के निम्नीकरण की पुनर्प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण पादप प्रजातियों के किस्मों का विकास किया जाएगा तथा कृषकों व राज्य वन विभागों को रोपित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। वृक्ष चारा, ईंधन-काष्ठ, अकाष्ठ वन उत्पाद, वन्य फलों, मृदा नमी, जैवविविधता, संरक्षण व व्याधियों के महत्वपूर्ण विषय-क्षेत्रों का भी निवारण किया जाएगा।

वन आनुवांशिक संसाधन संरक्षण महत्ता का एक अन्य क्षेत्र है जिस पर राष्ट्रीय स्तर संतति व भविष्य के वंशो के जीन भंडार के संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। राज्य रेड्ड प्लस कार्य योजना को तैयार करने के लिए राज्य वन विभागों का क्षमता निर्माण इस योजना का तीसरा घटक है। कृषि नीति की तर्ज पर वन नीति अनुसंधान सरकार को विभिन्न नीतियों की संकल्पना तथा वर्तमान वन नीतियों के प्रधावों के अध्ययन में आवश्यक नीति-निर्देशन प्रदान करेगा।

इस पहलु को योजना के चतुर्थ घटक द्वारा विवेचना की जाएगी। नवीन क्षेत्रों में वैज्ञानिक क्षमताओं की संवृद्धि के लिए मानव संसाधन विकास को इस योजना के माध्यम से संवोधित किया जाएगा। वताया कि परिषद पहले से ही 13 मुख्य नदियों की जीर्णोद्वार योजना के निर्माण पर कार्य कर रहा है।

SHAH TIMES 18 November, 2019

आईसीएफआरई अनुसंधान से सुधरेगी वनों की दशाः डॉ. गैरोला

कैंप में आईसीएफआरई को मिलेंगे 313 करोड़, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के साथ हुई बैठक में मिली स्वीकृति

किया गया है।

🔳 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के विकास के लिए किया जाएगा शोध कार्य, कुषकों को मिलेगा लाभ

पारिस्थितकी को वहन करने के लिए महों तथा भारतीय वनों एवं रोपणियों की उत्पादकता में संवृद्धि के लिए कार्य करेगा।

शाह टाइम्स संवाददाता देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (आईसीएफआरई) देहरादून, देशभर शक, आईसीएफआरई ने विस्तृत को सरकार द्वारा वानिकी अनुसंधान में फैले इसके नौ अनुसंधान संस्थानों योजना तथा पांच केन्द्रों के माध्यम से

संवहनीयता तथा उत्पादकता संवृद्धि राष्ट्रीय महत्ता के वानिकी अनुसंधान के लिए वानिकी अनुसंधान का सदढीकरण' को प्रस्तुत किया।

राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि नई दिल्ली में प्रकाश जावडेकर, प्रबंध निकाय ने आईसीएफआरई की वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की योजना का 313.67 करोड़ रुपये को अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रतिपुरक पूर्णतः अनुमोदित किया। भारत की वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्रमुख वानिकी परिषद् के इतिहास में प्राधिकरण की प्रबंध निकाय की यह एक ऐतिहासिक क्षण है कि इसके बैठक में डॉ. सुरेश गैरोला, महानिद. सुत्रपात से अब तक इस मुख्य योजना

आरोग्यता तथा वन आधारित लोगों की आजीविका एवं कृषि पर होगा। प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण के इस योजना के माध्यम से आईसीएफआरई तथा इसके संस्थान 31 मख्य अखिल भारतीय समन्वित अनसंधान परियोजनाओं पर कार्य करेंगे जिससे आरोग्यता व उत्पादकता में सुधार होगा तथा वनों एवं रोपणियों के निम्नीकरण की पुनर्प्राप्ति होगी।

किया जाएगा तथा कृषकों एवं राज्य राष्ट्रीय महत्व की अनसंधान वन विभागों को रोपित करने के लिए समस्याओं के सम्बोधन के लिए प्रदान किया जाएगा। वृक्ष चारा, वानिकी अनुसंधान को अति ईधन-काष्ठ, अकाष्ठ वन उत्पाद, आवश्यक वित्तपोषण की प्राप्ति होगी वन्य फलों, मुदा नमी, जैवविविधता, जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध देश के वन संरक्षण एवं व्याधियों के महत्वपूर्ण विषय-क्षेत्रों का भी निवारण किया जाएगा। वन आनुवंशिक संसाधन (एफ.जी.आर.) संरक्षण महत्ता का एक अन्य क्षेत्र है जिस पर राष्ट्रीय स्तर संतति व भविष्य के वंशों के जीन भण्डार के संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। "राज्य रेड कार्य योजना" को तैयार करने के लिए राज्य वन विभागों का क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के इस योजना का तीसरा घटक है। कृषि ''पारिस्थितिकीय एवं विस्तार के लिए अनुमोदित कुन्तकों एवं किस्मों का विकास नीति की तर्ज पर वन नीति अनुसंधान संबोधित किया जाएगा।

सरकार को विभिन्न नीतियों की संकल्पना तथा वर्तमान वन नीतियों के प्रभावों के अध्ययन में आवश्यक नीति निर्देशन प्रदान करेगा।

वानिकी अनुसंधान में प्रौद्योगिकीयों के लिए पहुँच (आउटरीच) कार्यक्रम सबसे कमजोर कड़ी रहा है। इसका सुदुढीकरण आईसीएफआरई की वानिकी विस्तार योजना के माध्यम से होगा। हितधारकों तक पहुंचना ही इस घटक की मुख्य विषय-वस्तु है। नवीन क्षेत्रों में वैज्ञानिक क्षमताओं की संवृद्धि के लिए मानव संसाधन विकास को इस योजना के माध्यम से